extension project initiated in 1985-86 and continued till March, 1995, covering 28 districts. The project was subsequently extended to 8 more districts of Central Uttar Pradesh. The project provided for strengthening of extension infrastructure, research support, training/information activities;

(ii) Training programmes for the farmers have been strengthened by establishing Krishi Vigyan Kendras in Eastern and Central Uttar Pradesh. Besides, Farmers Training Centres are providing training in advanced agricultural technology to the farmers;

(iii) Information on advanced agricultural technology to the farmers is also provided through farm exhibitions, print and electronic media, agricultural films, Kisan Melas, Farmers-Scientist Interaction, filed demonstrations, etc., organized by the State Agricultural Universities, State Departments of Agriculture and ICAR Institutes; and

(iv) Voluntary organizations have been involved on the process of transfer of technology to the farmers. One such NGO (Vanvasi Sewa Ashram) in Sonbhadra District of Eastern Uttar Pradesh, has been involved in the pilot scheme.

मध्य प्रदेश में साक्षरता

2016. **श्री दिलीप सिंह जूदेवः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में 1996 के अंत तक एक करोड़ दस लाख लोगों को साक्षर बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) राज्य में साक्षरता औसत इस समय कितनी है और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का औसत अन्य राज्यों की तुलना में कितना है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलाने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो 1995-96 के वित्तीय बजट में इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में साक्षरता औसत को ऊपर ऊठाने के लिए और क्या-क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) राज्यवार कोई लक्ष्य नहीं है।

(ख) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान अभी तक 340.15 लाख रु० की राशि संस्वीकृत की गई है।

(ङ) राज्य में औसत साक्षरता को बढ़ाने के लिए एक पूर्ण साक्षरता अभियानों को एक प्रमुख नीति के रूप में अपनाया गया है।

विवरण

राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के लिए साक्षरता दरें, 1991

भारत/राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश		साक्षरता दर 1991
भारत*		52.28
राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	44.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.59
3.	बिहार	38.48
4.	गोवा	75.51
5.	गुजरात	61.29
6.	हरियाणा	55.85
7.	हिमाचल प्रदेश	63.86
8.	कर्नाटक	56.04
9.	केरल	89.79
10.	मध्य प्रदेश	44.20
11.	महाराष्ट्र	64.87
12.	मणिपुर	59.89
13.	मेघालय	49.10
14.	मिजोरम	82.27
15.	नागालैंड	61.65
16.	उड़ीसा	49.09
17.	पंजाब	58.51
18.	राजस्थान	38.55
19.	सिक्किम	56.94
20.	तमिलनाडु	62.66
21.	त्रिपुरा	60.44
22.	उत्तर प्रदेश	41.60
23.	पश्चिम बंगाल	57.70
24.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	75.29
संघ शासित प्रदेश		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	73.02
2.	चंडीगढ़	77.81
3.	दादर व नगर हवेली	40.71
4.	दमन व दियू	71.20
5.	लक्षद्वीप	81.78
6.	पांडिचेरी	74.74

*असम व जम्मू कश्मीर शामिल नहीं।

गोबर तथा भूसे-पत्तों का उपयोग न किया जाना

2017. **श्री सोमपाल:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में पशुओं के गोबर, फसलों के बचे हुए भूसे-पत्ते आदि और शहरी क्षेत्रों में कूड़ा-करकट भारी मात्रा में बेकार ही चले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनके मद-वार आंकड़े क्या-क्या हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए इनका किस ढंग से उपयोग किया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) और (ख) देश में गोबर, फसलों के बचे हुए भूसे-पत्ते तथा कूड़ा-करकट की सही मात्रा का निर्धारण करना कठिन है। तथापि, यह अनुमान है कि फसलों के कूड़ा करकट, पशुओं के गोबर तथा शहर की रद्दी की वार्षिक उपलब्धता क्रमशः 275 मि०मी० टन, 1029 मि०मी० टन तथा 25 मिलियन मी० टन है। गोबर का लगभग 60-70 प्रतिशत और फसलों के कूड़ा-करकट तथा ग्रामीण रद्दी का 25 प्रतिशत प्रयोग मृदा के उपजाऊपन में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों से पता लगता है कि किसानों द्वारा लगभग 278 मिलियन मी० टन ग्रामीण तथा 6.4 मिलियन मी० टन शहरी कंपोस्ट खाद तैयार तथा प्रयोग की जाती है।

(ग) और (घ) आर्गेनिक खाद के मेल से उर्वरक